vinetur

लागत बढ़ने के बाद भारतीय मदिरा कंपनियां तेलंगाना में कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही हैं

Allied Blenders, Radico Khaitan और Tilaknagar पैकेजिंग, अनाज और ऊर्जा की बढ़ती लागत से राहत के लिए राज्य-दर-राज्य प्रयास कर रही हैं

सोमवार, 16 नवंबर 2026



The Hindu BusinessLine ने 15 नवंबर को खबर दी कि पैकेजिंग, अनाज और ऊर्जा की बढ़ती लागत से मुनाफे के मार्जिन पर दबाव पड़ने के कारण भारतीय मदिरा कंपनियां कई राज्यों में कीमतें बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इन चर्चाओं का प्रमुख केंद्र तेलंगाना बनकर उभरा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, कीमतों में संशोधन की मांग करने वाली कंपनियों में Allied Blenders, Radico Khaitan और Tilaknagar शामिल हैं। उनकी यह पहल भारत के आसवकों के सामने मौजूद एक बुनियादी समस्या को दिखाती है: लागत तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन खुदरा कीमतें अक्सर नहीं बढ़ पातीं। कई राज्यों में शराब की कीमतों पर कड़ा नियमन है और बढ़े हुए खर्च का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से पहले उत्पादकों को सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है।

इससे प्रमुख कच्चे माल की कीमतें बढ़ने पर मदिरा कंपनियां दबाव में आ जाती हैं। कांच की बोतलें, कार्टन और पैकेजिंग की अन्य सामग्रियां उत्पादन लागत का बड़ा हिस्सा होती हैं। अनाज और अन्य कृषि सामग्रियां भी महंगी हो सकती हैं, जबकि ऊर्जा की कीमतों का असर विनिर्माण, बोतलबंदी और परिवहन पर पड़ता है। जब इनमें से कई दबाव एक साथ आते हैं, तो उनका असर काफी बड़ा हो सकता है—खासकर उन बड़े ब्रांडों पर, जो कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।

मौजूदा चर्चाओं का केंद्र तेलंगाना दिखाई देता है। यह अहम है, क्योंकि भारत में स्पिरिट्स कारोबार पर राज्य सरकारों के फैसलों का असाधारण प्रभाव हो सकता है। शराब का नियमन राज्य स्तर पर होता है और हर बाजार में मंजूरी की प्रक्रिया, कर ढांचा और खुदरा व्यवस्था अलग-अलग होती है। किसी बड़े राज्य में अनुकूल फैसला उत्पादक को वहां अपना मार्जिन बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन वह अपने आप दूसरे राज्यों पर लागू नहीं होता। कंपनियों को अक्सर हर राज्य में अलग-अलग संशोधन की मांग करनी पड़ती है।

यह मामला केवल खुदरा कीमतें बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं है। कई पेय कंपनियों के लिए बढ़ती कच्चे माल की लागत की भरपाई कर पाने की क्षमता यह तय करती है कि वे मार्केटिंग, वितरण और नए उत्पादों में कितना निवेश कर सकती हैं। अगर कीमतों में संशोधन लंबे समय तक टलता रहे या उसे मंजूरी न मिले, तो उत्पादकों को बढ़ी लागत खुद उठानी पड़ सकती है, कम मुनाफा स्वीकार करना पड़ सकता है या अपने उत्पादों के मिश्रण में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों और छोटे क्षेत्रीय कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का संतुलन बदल सकता है।

यह दबाव स्पिरिट्स क्षेत्र के लिए खास तौर पर अहम है, जो भारत के पेय बाजार के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। कीमतों पर राज्यों का नियंत्रण कंपनियों की महंगाई के अनुरूप तेजी से कदम उठाने की क्षमता सीमित कर सकता है, जिसका असर मुनाफे के मार्जिन, विस्तार योजनाओं और प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। इन चर्चाओं के नतीजों पर व्यापक पेय उद्योग की भी करीबी नजर हो सकती है। इसमें बीयर निर्माता और शराब के अन्य उत्पादक भी शामिल हैं, जिन्हें कुछ बाजारों में इसी तरह की नियामकीय पाबंदियों का सामना करना पड़ता है।

अगर कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमतें बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकारों के लिए फैसला लेना अधिक जटिल हो सकता है। भारत में शराब कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कीमतों में बदलाव राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी हो सकता है। राज्यों को उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया, महंगाई की चिंताओं और राजस्व संबंधी पहलुओं का आकलन करना होगा, साथ ही उद्योग की इस दलील पर भी विचार करना होगा कि मौजूदा कीमतें अब उत्पादन लागत को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

यह नहीं बताया गया है कि संबंधित कंपनियां पूरे देश में एक समान बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। इसके बजाय, यह प्रक्रिया स्थानीय बातचीत और बाजार की स्थितियों पर आधारित दिखाई देती है। यह भारत के मदिरा उद्योग की बिखरी हुई प्रकृति को दर्शाता है, जहां नियामकीय अंतर ब्रांड की ताकत या मांग के रुझानों जितने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

मौजूदा पहल यह भी दिखाती है कि कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव के प्रति यह क्षेत्र अब भी कितना संवेदनशील है। बिक्री की मात्रा स्थिर रहने पर भी, अगर कंपनियां लंबे समय तक राज्य से मंजूर कीमतों में बदलाव नहीं कर सकतीं, तो मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए उत्पादकों के पास समय-समय पर कीमतों की समीक्षा की मांग करने का मजबूत कारण है, खासकर तब जब पैकेजिंग, कच्चे माल और ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी कई उत्पाद श्रेणियों की कमाई को प्रभावित करने लगे।

राज्य सरकारें मांगी गई बढ़ोतरी को मंजूरी देती हैं या नहीं, और देती हैं तो कितनी, इससे तय होगा कि आने वाले महीनों में आसवकों को कितनी राहत मिलेगी। फिलहाल, The Hindu BusinessLine की रिपोर्ट में बताई गई बातचीत से संकेत मिलता है कि लागत में महंगाई भारतीय मदिरा निर्माताओं के लिए अब भी एक बड़ा मुद्दा है और राज्य स्तर की मूल्य नीति इस कारोबार को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में बनी हुई है।